



00000000 00000000 0 00000000

खंडवा/नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सहजीवन संबंध के शादी की तरह कर शिष्टे में लाने और इस तरह उसे घरेलू हिंसा वरीधी कानून के तहत लाने के लिए कुछ दशा-नरिदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहजीवन में रहने वाले कदपति के बीच के विवाद का नपिटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। इस मामले में महिला ने रिश्ता खत्म होने के बाद पुरुष से गुजारे भत्ते की मांग की थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लोक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पहले आरिदेशों के ध्यान में रखते हुए अपने तरह का अनोखा फैसला भी सुना दिया है। खंडवा की लोक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पति और पत्नी के साथ अब सहजीवन की साथी महिला भी रहेगी। लोक अदालत में पछिले शनिवार आरि इस फैसले के तहत धार्मिक नगरी ओकरेश्वर के मांथाता नवासी पति बसंत माहूलाल और पत्नी शांता के साथ बसंत के साथ पछिले दस साल से सहजीवन (लवि इन रलेशनशिप) में रह रही रामकुमारी भी कही घर में रहेंगी।

लोक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सहजीवन को मान्यता देने के मद्देनजर यह फैसला दिया है। उसे अपने जीवन साथी के मकान, खेत व जमीन में आधा हिस्सा भी मलिया। इस फैसले में सबसे अनोखी बात तो यह है कि ककमरे में पति रहेगा, जो घर के बीच में है। वहीं, उसके दूसरी ओर के ककमरे में पत्नी और दूसरे कमरे में सहजीवन की साथी रहेगी। पति के कमरे का दरवाजा दोनों कमरों में खुलेगा और पति का कमरा दोनों की ओर पंद्रह-पंद्रह दिने के लिए खुलेगा।

खंडवा में हुई लोक अदालत ने समझौते के आधार पर मकान, खेत और पति को भी दोनों के बीच बराबर के हक के साथ बांट दिया है। पत्नी शांता ने दो साल पहले अपने पति बसंत माहूलाल की अदालत में शकियत की थी कि उसने लगभग दस साल से उसके अलावा कदूसरी महिला रामकुमारी से सहजीवन का रिश्ता कयम किया है और उसे घर में ही रख लिया है। मामला परिवार परामर्श केंद्र में भी गया, लेकिन वहां कोई हल नहीं निकल सका। लोक अदालत के विशेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने इसकी जांच कराई।

जांच रिपोर्ट में घरेलू हिंसा होना पाया गया। तब पति बसंत और सहजीवन साथी रामकुमारी को नोटिस जारी हुआ। महिला का पति बजिली विभाग में लाइनमैन है। उसने लोक अदालत में कहा कि सहजीवन अदालत की नजर में भी पाप नहीं है। इस लिए हमारी शर्तों पर भी ध्यान दिया जा। लोक अदालत के विशेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने तीनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद यह समझौता कराया।

सुप्रीम कोर्ट ने सहजीवन संबंधों के बारे में जो दशा-नरिदेश तय किए हैं उनमें संबंध की अवधि, कही घर में रहना और वित्तीय संसाधनों में सहभागिता सहित कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। न्यायमूर्त के स राधाकृष्णन और न्यायमूर्त पनिके चंद्र घोष की पीठ ने कहा कि हालांकि इस मामले में हमारे दिए आठ दशा-नरिदेश ही पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन इनसे ऐसे रिश्तों को तय करने के मामले में कुछ हद तक मदद जरूर मलि सकेगी।